है उतनी इसके द्वारा खरीद ली जाती है । विगत की तरह ही जै०सी०आई० ने अपने अवस्थापना तंत्र जिसमें चालू मौसम के खरीद प्रचालन के लिये गोदाम संबंधी व्यवस्था भी शामिल है, को पहले ही सुदृढ़ कर लिया है ।

पूर्ति विभाग का विकेन्द्रीकरण

984. **श्री अजीत सिंह :**
श्री सुशील बरोपा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्ति विभाग के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने और इस विभाग को समाप्त करने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप व्यय में कितनी बचत होने का अनुमान है ;

(ग) क्या उक्त विभाग के विभिन्न अनुभागों का विकेन्द्रीकरण करने तथा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्यत्र खपाये जाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई हैं ?

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य योजना की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) पूर्ति विभाग/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का समापन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा मांग किए जाने वाले सामान और उपस्करों की केन्द्रीयकृत खरीद के संबंध में नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही हैं ।

(ख) इसके फलस्वरूप व्यय में होने वाली किफायत का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया हैं, नीति की समीक्षा की जा रही हैं । यदि इस समीक्षा के फलस्वरूप कुछ कार्य केन्द्रीयकृत क्रय एजेंसी (पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय) से अन्य मंत्रालयों को सौंपा जाता हैं, तो अन्य विभागों/मंत्रालयों को कार्य सौंपे जाने पर उनसे संबंधित कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण उन विभागों/मंत्रालयों को किए जाने का प्रस्ताव हैं ताकि नौकरी में उनकी पदोन्नति के अवसरों में कोई कमी न आए ।

(ङ) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी ।

Loss of deposits by SBI

985. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the 'Economic Times' dated the 23rd July, 1990 to the effect that the State Bank of Inda is losing huge deposits to other banks every day;

(b) if so, whether the reasons for the same have been ascertained;

(c) what steps Government propose to take to arrest such huge outflow of deposits from the State Bank of India; and

(d) whether the Reserve Bank will also prescribe a uniform rate of interest to be paid by the different banks including SBI to its depositors on terms deposits?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) The said news item refers to a decline in State Bank of India's deposits, allegedly in the wake of introduction of Certificate of Deposits (CDS). Banks are permitted to issue CDS within permissible limits which at

present are equivalent to 2 per cent of the fortnightly average outstanding deposit in 1988-89. The interest on these CDS are determined freely by the concerned depositors and the bank and can vary accordingly. Although CDS are free from interest rate regulations, the bankwise limits on issue of CDS implies that there is a reasonable sharing of banks of the total market for CDS.

(d) The Reserve Bank of India has been issuing directives under the Banking Regulation Act from time to time regarding interest rates deposits and the compliance of the provisions of these directives is required to be strictly observed by the banks. The rates of Interest on deposits in various categories of accounts are as under:

Category of Account	(Per cent Per Annum)
1. Saving Account	5
2. Term Deposits	
(a) For deposits for 46 days and above but less than 1 year	8
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	9
(c) For deposits for 2 years and above	10

बोकारो स्टील प्लांट के प्राधिकारियों द्वारा दैनिक मजदूरों को कम मजदूरी का दिया जाना

986. श्री राम अवधेश सिंह : क्या इस्पात और खानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील प्लांट और "टिस्को" में प्रबन्धकों की पूर्ण जानकारी में श्रम मंत्रालय द्वारा इस्पात उद्योग में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों के लिए निर्धारित की गई 39/- रुपये की दैनिक मजदूरी के बजाय 29/- रुपये दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं । बोकारो इस्पात कारखानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाये गये अस्थायी श्रमिकों को न्यूनतम 55.24 रुपये दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। टिस्को द्वारा काम में लगाये गये अस्थायी कर्मचारियों को कम्पनी के स्थायी कर्मचारियों के बराबर भुगतान किया जाता है ।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

AICC(I)'s demand for waiving of agricultural loans

987. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether at the recent conference of the AICC(I) a demand was put forth to waive agricultural loans given to farmers artisans and landless labourers as assured by Government and to open fresh loans for farmers, especially in view of the fact that sowing season had already begun;

(b) if so, what is Government's response thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) Government of India have formulated the agricultural and Rural Debt Relief (ARDR) Scheme, 1990 for providing debt relief to farmers, landless cultivators, artisans and weavers upto Rs. 10,000/- by public sector banks and regional rural banks. for the operation of the scheme, Government of India have taken into account suggestions and demands put forth by the